

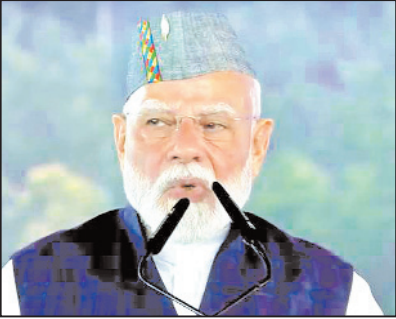
# मूक पत्रिका

## निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02    अंक - 280    बेमेतरा, शनिवार 06 जून 2026    रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित    कुल पेज - 08    मूल्य - 5 रुपये    डाक पंजीयन- दुर्गा/1743290201/2025-27

# पीएम मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया कर्नाटक से बंगाल तक का जिक्र

गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरें पर ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान के तहत चल रही विकास परियोजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने सूरत के हजीरा के अलावा अंतरराज्यीय रोड नेटवर्क का उल्लेख करते हुए कहा कि कुछ लोग देश में निराशा का माहौल बनाने में लगे हैं। पीएम मोदी ने विपक्षी राजनीतिक दलों को आड़े हाथों लिया और बिना किसी का नाम लिए कहा कि ये लोग निराशा का माहौल बनाने के अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक भी बनाते हैं। उन्होंने कांग्रेस या राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा, कुछ लोग भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली सफ लता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा के दौरान भी उन्हें बंगाल के जनादेश का जिक्र सुनने



को मिला। हाल ही में कर्नाटक में बदले मुख्यमंत्री का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस राज्य में भी कांग्रेस को लेकर जनता में भारी आक्रोश है। पीएम मोदी ने भाजपा को मिलने वाली राजनीतिक सफलता

का उल्लेख करते हुए कहा कि देश अराजकता, अनिश्चितता और निराशा को पसंद नहीं करता। कांग्रेस पिछले 12 वर्षों से अराजकता और अनिश्चितता फैला कर अपने लिए अवसर तलाश रही है, लेकिन देश की जनता बार-बार करारा जवाब दे रही है। आप लोगों ने तो कांग्रेस को हाशिए पर धकेल दिया है। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां की जनता कांग्रेस के कुशासन से तंग आ चुकी है। हिमाचल में हुए निकाय चुनाव का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, वहां की जनता ने भी कांग्रेस के कुशासन को नकार दिया। पिछले साल हरियाणा और पंजाब की जनता ने भी कांग्रेस को स्पष्ट संदेश दिया है। जनता ने साफकर दिया है कि कांग्रेस की अराजकता में अवसर खोजने की राजनीति नहीं चलेगी।

## प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत के जैव विविधता संरक्षण प्रयासों पर प्रकाश डाला

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की समृद्ध जैविक विविधता का उल्लेख करते हुए वन्यजीव संरक्षण एवं वन विस्तार में देश की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और कहा कि निरंतर प्रयासों ने देश भर में कमजोर प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने में मदद की है। मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत अपनी विशाल जैव विविधता और विविध पारिस्थितिक तंत्रों पर गर्व करता है जो असंख्य प्रजातियों के साथ-साथ लाखों आजीविका का समर्थन करते हैं। प्रधान मंत्री ने

कहा, भारत में हमें अपनी जैविक विविधता पर बहुत गर्व है। हमारे विविध पारिस्थितिकी तंत्र अनगिनत प्रजातियों और आजीविका का समर्थन करते हैं। सरकार की संरक्षण पहलों का उल्लेख करते हुए, श्री मोदी ने लुप्तप्राय और कमजोर वन्यजीव प्रजातियों की रक्षा के उद्देश्य से विशेष पुनर्प्राप्ति कार्यक्रमों की सफलता की बात की। उन्होंने कहा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हिम तेंदुआ, स्लॉथ बीयर और चीतों के संरक्षण प्रयासों ने प्रदर्शित किया है कि दीर्घकालिक प्रतिबद्धता वन्यजीव आबादी और पारिस्थितिक आवासों के पुनरुद्धार में कैसे योगदान दे सकती है।

उन्होंने कहा, विशेष पुनर्प्राप्ति में हमारे प्रयास भी उल्लेखनीय रहे हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हिम तेंदुआ, स्लॉथ बीयर और चीता के संरक्षण प्रयासों ने इस बात की झलक दी है कि निरंतर प्रतिबद्धता वन्यजीवन और पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने में कैसे मदद कर सकती है। प्रधान मंत्री ने पिछले साल शुरू किए गए ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के प्रभाव का भी हवाला दिया, जो नागरिकों को अपनी माताओं के सम्मान में पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

## ‘स्मार्ट बार्डर’ अवधारणा का कार्य अंतिम चरण में इसका पायलट प्रोजेक्ट जल्द शुरू किया जायेगा : शाह

नयी दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं की निगरानी के लिए सरकार की ‘स्मार्ट बार्डर’ अवधारणा का कार्य अंतिम चरण में है और इसका पायलट प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू किया जायेगा। शाह ने त्रिपुरा में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की लंकापुरा सीमा चौकी का निरीक्षण करने के बाद जवानों के साथ संवाद किया। उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अगरतला में वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत ‘अगर’ पौधे का रोपण किया। सीमाओं पर अनेक प्रकार की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया

है कि जहां-जहां सीमा पर बीएसएफ और सशस्त्र सीमा बल तैनात हैं, वहां पर ‘स्मार्ट बार्डर’ का निर्माण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत, स्थानीय प्रशासन, प्रौद्योगिकी और जवानों के परिश्रम को साथ में लेते हुए सीमाओं को अभेद्य बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट बार्डर की अवधारणा पर चर्चा अंतिम चरण में है और इसका पायलट प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू किया जायेगा। उन्होंने कहा , हम एक साथ देश की अलग-अलग सीमाओं पर सात या आठ स्थानों पर इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। पायलट प्रोजेक्ट में जो भी शुरूआती समस्याएं

आएंगी उन्हें दूर कर पूरी सीमा को स्मार्ट बार्डर बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एसपी, गांव के पटवारी और सरपंच की भी भूमिका होगी। जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों के स्थानीय प्रशासन को हम इस कॉन्सेप्ट में समाहित नहीं करते, तब तक हम सीमा को अभेद्य नहीं बना सकते। अगर हम आइसोलेशन में सीमा की सुरक्षा की कल्पना करते हैं वो कभी सफल नहीं हो सकती। शाह ने कहा कि त्रिपुरा फ्रंटियर देश की सीमा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सीमा पर बाड़ के आधुनिकीकरण के लिए 15 वर्ष से पुरानी लगभग 650 किलोमीटर की बाड़ में से 119 किलोमीटर नई बाड़ को भी मंजूरी दी गयी है।

## नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियां तेज, मुख्य सचिव ने कलेक्टरों-एसपी को दिए व्यापक निर्देश

रायपुर। 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी-2026 पुनर्परीक्षा के संचारु एवं सुरक्षित संचालन को लेकर मुख्य सचिव विकासशील ने सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने परीक्षा के दौरान राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) और केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। मंत्रालय महानदी भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों का पूर्व निरीक्षण करने तथा सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि योग दिवस से संबंधित गतिविधियों का परीक्षा संचालन पर किसी प्रकार का प्रतिकूल

प्रभाव न पड़े। उन्होंने परीक्षा केंद्रों तक अभ्यर्थियों की सुगम पहुंच, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को संयुक्त टीमों के माध्यम से अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग कर उन्हें परीक्षा को लेकर अनावश्यक तनाव से मुक्त करने पर भी जोर दिया। मुख्य सचिव ने 20 जून को परीक्षा संचालन से संबंधित सभी व्यवस्थाओं की मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसकी तैयारी पूर्व से ही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि प्रश्नपत्र और ओएमआर शीट का परिवहन वायुसेना के माध्यम से किया जाएगा, इसलिए इनके सुरक्षित भंडारण और परिवहन के लिए जिला प्रशासन एवं

पुलिस को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। बैठक में प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्ष स्थापित कर परीक्षा दिवस पर उसे सक्रिय रखने के निर्देश भी दिए गए, ताकि परीक्षा संचालन की प्रभावी निगरानी की जा सके। बैठक में एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ में नीट यूजी-2026 पुनर्परीक्षा 19 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसके लिए 127 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से परीक्षा के सफल संचालन के लिए समन्वित प्रयास करने का आग्रह किया। बैठक में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के सचिव बसवराज एस., राज्य नोडल अधिकारी पीयूष शुक्ला, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, पुलिस विभाग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के अधिकारी तथा संबंधित जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए।

## वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बिस्तराव, इस समय का सबसे बड़ा जोखिम : आरबीआई गवर्नर

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि अर्थव्यवस्था के सामने इस समय सबसे बड़ा जोखिम वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों के चलते वैश्विक आपूर्ति की श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधान है क्योंकि इसका अवसर मुद्रास्फीति पर पड़ता है। मल्होत्रा आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की द्वैमासिक समीक्षा बैठक के बाद परंपरागत संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। आरबीआई की द्वैमासिक समीक्षा रिपोर्ट में जगह-जगह जोखिमों के उल्लेख के बारे में पूछे गये स्पष्टीकरण पर उन्होंने कहा कि ऐसी कई बातें हैं जो मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। इनमें भू-राजनीतिक संघर्ष और मानसून की कमी के अनुमान जैसे जोखिम शामिल हैं। उन्होंने कहा, ‘देखना है कि आगे स्थिति कैसी बनती है, पश्चिम एशिया में संघर्ष कब खत्म होता है और आपूर्ति श्रृंखलाओं की बहाली में कितना समय लगता है।

## राष्ट्रपति ने आईटीडीपी भैंसदेही को राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा

बैतूल (ए)। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) भैंसदेही को जनजातीय क्षेत्रों में उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव-2026 में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने आईटीडीपी भैंसदेही को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पांच लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की। यह सम्मान एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया गया। परियोजना की ओर से सहायक आयुक्त एवं प्रभारी परियोजना प्रशासक विवेक कुमार पाण्डेय ने सम्मान ग्रहण किया। इस उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उर्डेक, जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव तथा बैतूल कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने परियोजना दल को बधाई दी। आईटीडीपी भैंसदेही ने भैंसदेही, भीमपुर और आठनेर विकासखंडों के 231 जनजातीय



बहुल गांवों में अभिसरण आधारित विकास मॉडल को प्रभावी रूप से लागू किया है। परियोजना के अंतर्गत आधारभूत संरचना, आजीविका, सामाजिक कल्याण और सुशासन से जुड़े कार्यों को एकीकृत रूप से संचालित किया गया। धरती आबा अभियान, आदि कर्मयोगी अभियान तथा जनजातीय कार्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन के माध्यम से आवास, पेयजल, सड़क संपर्क और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की गई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तीनों विकासखंडों में 5,112 आवास स्वीकृत किए गए हैं,

जबकि जल जीवन मिशन के माध्यम से 46 हजार से अधिक जनजातीय परिवारों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 139 कारीगरों को लाभ के लिए स्वीकृति दी गई है। वहीं किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सिंचाई उपकरण और कृषि प्रदर्शन जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 1,992 गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं का पंजीकरण किया गया। साथ ही प्रायोजन एवं बाल आशीर्वाद योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों को सहायता उपलब्ध कराई गई। क्षेत्र के 362 आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन का कार्य भी किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार सामुदायिक भागीदारी और जागबदेह प्रशासन पर आधारित यह मॉडल जनजातीय विकास के क्षेत्र में देश के लिए एक उदाहरण के रूप में उभरा है।

## अमेरिकी सीनेट ने गृह सुरक्षा विभाग के लंबे समय से रुके बजट को मंजूरी दी

वॉशिंगटन। अमेरिकी संसद के उच्च सदन (सीनेट) ने रात भर चली बहस के बाद गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) की प्रवास नियंत्रण एजेंसियों के लिए लंबे समय से रुके धन आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सांसदों ने एक मामूली अंतर (52 के मुकाबले 47 मतों) से लगभग 70 अरब डॉलर के इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। इससे सीमा सुरक्षा और प्रवास नियंत्रण विभाग (आईसीडी) को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शेष कार्यकाल के लिए जरूरी बजट मिल गया है। अलास्का से रिपब्लिक पार्टी की सांसद लिसा मुकोव्स्की ने इस प्रस्ताव का विरोध करने में विपक्षी दल का साथ दिया।

अब यह विधेयक मंजूरी के लिए संसद के निचले सदन (प्रतिनिधि सभा) के पास जाएगा। सीबीएस न्यूज के अनुसार, सत्तारूढ़ दल के सांसदों ने इस प्रस्ताव को ‘बजट सामंजस्य’ (बजट रिकन्सिलिएशन) प्रक्रिया

के जरिए आगे बढ़ाया। अमेरिकी संसद में यह आर्थिक और कर से जुड़े कानूनों को बिना विपक्षी समर्थन के तेजी से पास कराने की एक विशेष प्रक्रिया है। इस विधेयक को अंतिम मंजूरी 18 घंटे से अधिक समय तक चली मैराथन मतदान प्रक्रिया (वोट-अ-रामा) के बाद मिली, जिसके दौरान सांसदों ने दर्जनों संशोधनों पर विचार किया। हालांकि इस विधेयक का मुख्य ध्यान प्रवास नियंत्रण को धन देना था, लेकिन बहस का एक बड़ा हिस्सा न्याय विभाग के विवादास्पद ‘उत्पीड़न विरोधी’ कोष (एंटी-वेपनाइजेशन) पर केंद्रित रहा।

## राहुल की लोगों से अंडमान-निकोबार बचाने के अपने अभियान से जुड़ने की अपील

नयी दिल्ली (ए)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार परियोजना का विरोध करते हुए देशवासियों से अंडमान-निकोबार द्वीप समूह को बचाने के उनके अभियान से जुड़ने और याचिका पर हस्ताक्षर करने की अपील की है। गांधी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मैं अंडमान और निकोबार के विनाश

के खिलाफ पूरी शक्ति के साथ खड़ा हूँ। अंडमान और निकोबार भारत की सबसे अनमोल प्राकृतिक धरोहर हैं। वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने देश के नागरिकों से इस अभियान में जुड़ने के लिए अपील करते हुए कहा, मेरे साथ जुड़िए, याचिका पर हस्ताक्षर कीजिए और इस अमूल्य संपत्ति को बचाने की लड़ाई का हिस्सा बनिए।

## आरबीआई ने रेपो दर स्थिर रखी

मुंबई (ए)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बढ़ती महंगाई के मद्देनजर शुक्रवार को अल्पावधि कर्ज की अपनी नीतिगत दर रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25 प्रतिशत पर स्थिर रखने का फैसला किया। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की आज समाप्त तीन दिवसीय बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एक बयान में यह जानकारी दी।

## नागरिकों से हरित, स्वच्छ और समृद्ध भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने की अपील की

## पर्यावरण संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के प्रति नैतिक जिम्मेदारी : मुख्यमंत्री साय

रायपुर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए पर्यावरण संरक्षण को आने वाली पीढ़ियों के प्रति नैतिक जिम्मेदारी बताया और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सामूहिक भागीदारी का आह्वान किया। साय ने संदेश में कहा कि प्रकृति मानव जीवन का आधार है और हमारी संस्कृति, सभ्यता तथा अस्तित्व की सबसे बड़ी संरक्षक भी है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल शासकीय या सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने नागरिकों से हरित, स्वच्छ और समृद्ध भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए



संकल्पित होने की अपील की। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष किरण देव ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लिया। एक पौधा, एक संकल्प : हरित भविष्य की ओर एक सार्थक कदम थीम के तहत पौधरोपण करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखना समय

की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वृक्षारोपण केवल एक अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है। उन्होंने प्रदेशवासियों, विशेषकर युवाओं से अधिकाधिक पौधे लगाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आने का आह्वान किया। भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठकरे परिसर में भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। जम्वाल ने कहा कि प्रकृति और प्रगति के बीच संतुलन बनाए रखना ही सतत विकास का आधार है।

## कांग्रेस मुद्दों के अभाव में लगा रही है निराधार आरोप : साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के उस आरोप को खारिज किया है, जिसमें कहा गया था कि भाजपा लाठी के दम पर शासन कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह इस प्रकार के आरोप लगा रही है। मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा के दौरान बिलासपुर में कहा, कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए गलत आरोप लगा रही है। किसी भी तरह के अपराध होने पर उसकी जांच होती है। एक्शन लिया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार कानून-व्यवस्था के मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है तथा अपराध से जुड़े मामलों में नियमानुसार जांच और कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हाल ही में संपन्न नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनावों के परिणामों पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सकारात्मक जनसमर्थन मिला है और तीन नगर पंचायतों में पार्टी समर्थित अध्यक्ष तथा पार्षद प्रत्याशियों ने सफलता हासिल की है। साय ने कहा कि इन चुनावों में विजय प्राप्त करने वाले सभी जनप्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी जाती हैं। साथ ही उन्होंने चुनावी प्रक्रिया के दौरान सक्रिय भूमिका निभाने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के प्रयासों की भी सराहना की।

## भांगर बम विस्फोट मामले में एनआईए ने की छापेमारी, तीसरा आरोपी गिरफ्तार

नयी दिल्ली (ए)। केंद्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के भांगर बम विस्फोट मामले में व्यापक तलाशी अभियान चलाकर एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। धमाके में मारे गये और बम बनाने के घायल हुए आरोपियों को लाने-ले जाने के लिए इस्तेमाल की गयी स्कॉर्पियो कार के ड्राइवर सैनूर मोल्ला की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में कुल गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर तीन हो गयी है। यह घटना पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले की है जब आरोपी और उसके सहयोगी देस बम बना रहे थे इस मामले के मुख्य संदिग्ध और साजिशकर्ता पूर्व विधायक तथा भगोड़े शौकत मोल्ला के आवास और संदिग्ध ठिकानों सहित कुल आठ स्थानों

पर आज तलाशी ली गयी। इसके अलावा सदिग्धों से जुड़े परिसरों की भी तलाशी ली गयी। इसमें कई आपत्तिजनक सामग्रियां, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और डिजिटल साक्ष्य जब्त किये गये हैं। इन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। एनआईए जांच से पता चला है कि विस्फोट के बाद आरोपी सैनूर मोल्ला ने ही उस स्कॉर्पियो वाहन को चलाया था, जिसका इस्तेमाल धमाके में मारे गये एक व्यक्ति और अन्य घायलों को ले जाने के लिए किया गया था। वह मृतक और घायलों को पहले एक स्थानीय अस्पताल और फिर एक अन्य स्थान पर ले गया था, जहां उसने उन्हें एम्बुलेंस में डाल दिया था।











# संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी ने एक बार फिर दहेज प्रथा की भयावहता को सामने ला दिया है। कड़े कानूनों के बावजूद दहेज उपीड़न और दहेज हत्या के मामले यह संकेत देते हैं कि समस्या केवल कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक मानसिकता और व्यवस्था की भी है। कोई भी समाज तभी सभ्य और समग्र रूप से विकसित कहलाता है, जब उसमें ऊंच-नीच और किसी तरह के मतभेद की कोई दीवार नहीं होती तथा सबको उसके हिस्से का अधिकार मिलता है। मगर इसे विंडबना ही कहा जाएगा कि आजादी के दशकों बाद भी भारतीय

समाज में ऐसी कुप्रथाएं अपनी जड़ें जमाए हुए हैं, जहां पुरुषवादी मानसिकता के कारण महिलाओं को कमतर आंका जाता है और उन्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है।दहेज प्रथा भी इनमें से एक है, जिसके खिलाफ सख्त कानून होने के बावजूद उस पर रोक नहीं लग पा रही है। दहेज के लिए महिला का उपीड़न करने या उसकी हत्या कर देने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। ऐसे ही एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि एक तरफ लड़की के परिवार से उपहार के नाम पर मोटी

रकम ली जाती है और फिर उन्हें भिखारी भी कहा जाता है, यह स्थिति बेहद शर्मनाक है। शीर्ष अदालत ने स्पष्टकहा कि समाज में यह संदेश जाना चाहिए कि दहेज के लिए बहु और उसके परिवार को प्रताड़ित करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।सवाल यह है कि जब देश में दहेज के खिलाफ कड़े कानूनी प्रावधान लागू हैं, तो आखिर इस कुरीति पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? जाहिर है कि यह हमारे शासकीय तंत्र और सामाजिक व्यवस्था में खामियों का ही नतीजा है, जिसका खामियाजा महिलाओं और उनके परिवार को भुगतना पड़ रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

(एनसीआरबी) के आंकड़ों के मुताबिक, देश में वर्ष 2017 में दहेज हत्या के 7,466 मामले दर्ज हुए थे, जबकि वर्ष 2024 के दौरान ऐसे 5,737 मामले दर्ज किए गए।इसी तरह वर्ष 2023 में दहेज प्रताड़ना से जुड़े 15 हजार से अधिक मामले दर्ज हुए। एनसीआरबी के ही अनुसार, 2024 में दहेज हत्या के 5,737 मामले दर्ज किए गए। यानी वास्तविक स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि कई मामलों में महिलाएं मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करती हैं, लेकिन सामाजिक दबाव, परिवार की बदनामी और

जागरूकता के अभाव में वे पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करा पातीं।इसमें दोराय नहीं कि दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए कानूनी और सामाजिक मोर्चे दोनों पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। जब तक समाज की सोच में बदलाव नहीं आएगा और महिलाओं को व्यापक स्तर पर उनके अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं किया जाएगा, तब तक कानून बनाने का मकसद और उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी अधूरा ही रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने भी साफ कहा है कि आखिर लड़के शादी क्यों करते हैं, अगर बाद में लड़की और उसके परिवार का अपमान ही

करना होता है।दहेज के लिए मानसिक और आर्थिक दबाव डालना एक गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। यह विचित्र बात है कि समाज में दहेज प्रताड़ना को सामान्य घटना मान लिया जाता है, जिस कारण कई बार पुलिस की ओर से भी पीड़ित पक्ष की शिकायत दर्ज करने के बजाय दोनों पक्षों में सुलह कराने को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे में जरूरत इस बात की भी है कि दहेज से जुड़े मामलों को हर स्तर पर गंभीरता से लिया जाए और सरकारी जांच तंत्र में व्याप्त खामियों को दुरुस्त कर उसे संवेदनशील एवं जवाबदेह बनाया जाए।

**अधिकांश देशों में सदियों से माता-पिता का सम्मान करने की परंपरा रही है। माता-पिता ईश्वर का सबसे अच्छा उपहार हैं। जीवन में कोई भी माता-पिता की जगह नहीं ले सकता। वे सच्चे शुभचिंतक हैं। लेकिन मानव इतिहास में कभी भी परिवार और माता-पिता की भूमिका इतनी चुनौतीपूर्ण नहीं रही, जितनी आज है। तकनीकी क्रांति ने जीवन को सुविधाजनक बनाया है, लेकिन मानवीय संबंधों को नई परीक्षाओं के सामने भी खड़ा कर दिया है। मोबाइल, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस युग में बच्चों की दुनिया तेजी से बदल रही है। ज्ञान के स्रोत घर और विद्यालय से निकलकर डिजिटल मंचों तक पहुंच गए हैं।**

**(ललित गार्ग)**

अधिकांश देशों में सदियों से माता-पिता का सम्मान करने की परंपरा रही है। माता-पिता ईश्वर का सबसे अच्छा उपहार हैं। जीवन में कोई भी माता-पिता की जगह नहीं ले सकता। वे सच्चे शुभचिंतक हैं। लेकिन मानव इतिहास में कभी भी परिवार और माता-पिता की भूमिका इतनी चुनौतीपूर्ण नहीं रही, जितनी आज है।

विश्व के अधिकतर देशों की संस्कृति में माता-पिता का रिश्ता सबसे बड़ा एवं प्रगाढ़ माना गया है। भारत में तो इन्हें ईश्वर का रूप माना गया है। माता-पिता को उनके बच्चों के लिए किए गए उनके काम, बच्चों के प्रति उनकी निस्वार्थ प्रतिबद्धता और इस रिश्ते को पोषित करने के लिए उनके आजीवन त्याग के लिए सम्मान और सराहना देने के लिए प्रतिवर्ष विश्व माता-पिता ( अभिभावक ) दिवस 1 जून को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र ( यूएन ) का पालन दिवस है। यह दिन हमें उस महान शक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी अवसर देता है, जिसके कारण मानव जीवन का अस्तित्व, विकास और संस्कार संभव हो पाते हैं। वर्ष 2026 की थीम ‘माता-पिता के लिए एक साथ’ एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। यह केवल माता-पिता के सम्मान का आह्वान नहीं करती, बल्कि पूरे समाज, समुदायों, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारों को यह प्रेरणा देती है कि वे माता-पिता की भूमिका को समझें, उनके साथ खड़े हों और उनके दायित्वों को निभाने में सहयोग करें।

अधिकांश देशों में सदियों से माता-पिता का सम्मान करने की परंपरा रही है। माता-पिता ईश्वर का सबसे अच्छा उपहार हैं। जीवन में कोई भी माता-पिता की जगह नहीं ले सकता। वे सच्चे शुभचिंतक हैं। लेकिन मानव इतिहास में कभी भी परिवार और माता-पिता की भूमिका इतनी चुनौतीपूर्ण नहीं रही, जितनी आज है। तकनीकी क्रांति ने जीवन को सुविधाजनक बनाया है, लेकिन मानवीय संबंधों को नई परीक्षाओं के सामने भी खड़ा कर दिया है। मोबाइल, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस युग में बच्चों की दुनिया तेजी से बदल रही है। ज्ञान के स्रोत घर और विद्यालय से निकलकर डिजिटल मंचों तक पहुंच गए हैं। ऐसे समय में माता-पिता की भूमिका केवल पालन-पोषण तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि वे बच्चों के भावनात्मक संतुलन, नैतिक विकास, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक चेतना के प्रमुख संरक्षक बन गए हैं। वे केवल जीवन देने वाले नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाले हैं। दुनिया के हर समाज में माता-पिता को सम्मान दिया जाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति ने उन्हें विशेष रूप से देवत्व का स्थान प्रदान किया है। हमारे उपनिषदों का उद्धोष ‘मातृ देवो भव:, पितृ देवो भव:’ - मानव सभ्यता के श्रेष्ठतम जीवन मूल्यों में से एक है। मां अपने वात्सल्य, करुणा, त्याग और ममता से जीवन को सींचती है, जबकि पिता अपने परिश्रम, अनुशासन, संरक्षण और संघर्ष से भविष्य की मजबूत नींव रखता है। इसी कारण भारतीय परिवार व्यवस्था सदियों तक विश्व के लिए आदर्श बनी रही है।

हमारे इतिहास और पुराणों में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो माता-पिता के सम्मान और सेवा की प्रेरणा देते हैं। श्रवण कुमार की कथा केवल एक पुत्र की कहानी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। अपने वृद्ध और दृष्टिहीन माता-पिता को कंधों पर बैठाकर तीर्थयात्रा करने वाले श्रवण कुमार ने उन्हें विशेष रूप से देवत्व का स्थान सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्रीराम ने पिता दशरथ के वचन की रक्षा के लिए राज्य, वैभव और सुखों का त्याग कर वनवास स्वीकार किया। यह केवल आज्ञापालन नहीं था, बल्कि माता-पिता के सम्मान को सर्वोच्च मानने का संदेश था। महाभारत, रामायण और जैन तथा बौद्ध साहित्य में भी माता-पिता के प्रति श्रद्धा को जीवन का सर्वोच्च मूल्य माना गया है। भगवान के रूप में माता-पिता हमारे



आवश्यकता है। वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या, पारिवारिक विघटन और पीढ़ियों के बीच बढ़ती दूरी हमें यह सोचने के लिए विवश करती है कि कहीं आधुनिकता की दौड़ में हम अपने मूल्यों को तो नहीं खो रहे हैं। आर्थिक सफलता, सामाजिक प्रतिष्ठा और तकनीकी उपलब्धियां तभी सार्थक हैं, जब उनके साथ मानवीय संवेदनाएं भी जीवित रहें। जिस घर में माता-पिता सम्मानित होते हैं, वहां संस्कारों की धारा बहती है, जहां उनका उपेक्षित होना प्रारंभ होता है, वहां परिवार की आत्मा कमजोर पड़ने लगती है। वास्तव में माता-पिता किसी भी बच्चे के प्रथम गुरु होते हैं। विद्यालय ज्ञान दे सकता है, लेकिन जीवन जीने की कला, संघर्ष का साहस, प्रेम का भाव, करुणा की संवेदना और नैतिकता की नींव माता-पिता ही रखते हैं। वे अपने बच्चों के लिए अनगिनत त्याग करते हैं, अनेक सपनों का परित्याग करते हैं और बिना किसी अपेक्षा के उनके उज्ज्वल भविष्य

की सबसे मजबूत नींव है। यदि हम एक संवेदनशील, संस्कारित और समृद्ध समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें माता-पिता के सम्मान और सशक्तिकरण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल करना होगा। इस दिवस को मनाने की सार्थकता तभी है जब हम केवल भारत में ही नहीं है बल्कि विश्व में अभिभावकों के साथ होने वाले अन्याय, उपेक्षा और दुर्व्यवहार पर लगाम लगाने की भी है। प्रश्न है कि दुनिया में अभिभावक दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों हुई? क्यों अभिभावकों की उपेक्षा एवं प्रताड़ना की स्थितियां बनी हुई है? चिन्तन का महत्वपूर्ण पक्ष है कि अभिभावकों की उपेक्षा के इस गलत प्रवाह को कैसे रोकें। क्योंकि सोच के गलत प्रवाह ने न केवल अभिभावकों का जीवन दुश्गर कर दिया है बल्कि आदमी-आदमी के बीच के भावात्मक फासलों को भी बढ़ा दिया है। ( यह लेखक के अपने विचार है )।

# कोठियां, काफिले और स्मारक- दिल्ली में जमीन की नहीं, उसके इस्तेमाल की कहानी ज्यादा दिलचस्प है

**तो अगर इस एक क्लब की जमीन सरकार वापस लेने को तैयार है, इस आधार पर कि सार्वजनिक जमीन कानिजी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो क्यों नहीं पूछते हैं हम कि इस आधार पर सरकारी अशोक होटल और सम्राट होटल भी बंद किए जाएं? ये भी तो प्रधानमंत्री के आवास के कुछ ज्यादा नजदीक हैं और उनकी ऊंची छतों से कोई प्रधानमंत्री के आवास पर हमला करना चाहे, तो जिमखाना क्लब से कहीं ज्यादा आसान है। प्रधानमंत्री आवास के पीछे कई कोठियां हैं, जिनमें मंत्री और सांसद रहते हैं ।**

**(तवलीन सिंह)**

फिलहाल प्रधानमंत्री के कहने पर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं उनके मुख्यमंत्री और मंत्री। कभी किसी मुख्यमंत्री की पत्नी साइकिल पर सवार होकर निकलती है टीवी पत्रकारों के सामने, तो कभी कोई मुख्यमंत्री स्कूटर पर सवार होकर निकलते हैं पत्रकारों को दिखाने के लिए। जिमखाना क्लब को बंद करने की कोशिश ने एक ऐसा पिटारा खोल दिया है, जिसमें से निकल रहे हैं कई अहम सवाल। जिनको अभी तक इस विवाद के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, उनके लिए संक्षेप में पहले बता दूं कि मुद्दा क्या है। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बनकर लुटियंस दिल्ली में रहने लगे हैं, उन्होंने दिल लगाकर कोशिश की इस सभ्रांत रियायशी इलाके की शकल बदलने की।इस प्रयास में उन्होंने नया संसद भवन बनाया है रायसीना पहाड़ी पर, और जो सरकारी दफ्तर बने थे अंग्रेजों के जमाने में, उनको खाली कर नए आधुनिक भवनों में भेज दिया है। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की ओर जो सड़क जाती है, उसका नाम राजपथ से बदलकर कर्तव्यपथ रखा है और अपने नए कार्यालय को ‘सेवा तीर्थ’ का नाम दिया है।

कुछ वर्ष पहले जब जिमखाना क्लब की कार्यसमिति में उन्होंने कुछ सरकारी अफसर नियुक्त किए थे, तो ऐसा लगा था इस क्लब के सदस्यों को कि यह पहला कदम है उस सरकारी जमीन को वापस लेने के लिए, जिस पर यह क्लब बना था 113 साल पहले। ऐसा ही हुआ पिछले सप्ताह, जब क्लब को सूचना भेजी कि जून के पहले सप्ताह तक क्लब सरकार को जमीन वापस करे, जिसके लिए सालाना सिर्फ हजार रुपए का किराया सरकार को मिलता रहा है।

क्लब ने इस सूचना को अदालत में चुनौती दी है और ऐसा हो सकता है कि उसको थोड़ी-बहुत मोहलत मिल जाए, लेकिन दिल्ली में अफवाहें अब यह भी उड़ रही हैं कि सरकार का इरादा है प्रधानमंत्री आवास के पास रेसकोर्स

और पोलो ग्राउंड की जमीन भी वापस लेने का। यहां याद दिलाना चाहती हूं कि लुटियंस दिल्ली की सारी जमीन सरकारी है, जो लोगों को सौ साल या 99 साल की लीज पर दी गई है।

तो अगर इस एक क्लब की जमीन सरकार वापस लेने को तैयार है, इस आधार पर कि सार्वजनिक जमीन का निजी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो क्यों नहीं पूछते हैं हम कि इस आधार पर सरकारी अशोक होटल और सम्राट होटल भी बंद किए जाएं? ये भी तो प्रधानमंत्री के आवास के कुछ ज्यादा नजदीक हैं और उनकी ऊंची छतों से कोई प्रधानमंत्री के आवास पर हमला करना चाहे, तो जिमखाना क्लब से कहीं ज्यादा आसान है। प्रधानमंत्री आवास के पीछे कई कोठियां हैं, जिनमें मंत्री और सांसद रहते हैं और जिमखाना क्लब के सामने है इंदिरा गांधी का पुराना घर, जो उनके बेटे ने स्मारक बना दिया था और खुद उस घर में रहने लगे, जो आज प्रधानमंत्री आवास कहलाता है। देश के पहले प्रधानमंत्री रहा करते थे तीनमूर्ति भवन में, जिसको उनकी बेटी ने स्मारक बना दिया था अपने पिता की याद में।

सच तो यह है कि इस पहले घर को स्मारक न बनाया होता, तो प्रधानमंत्री का स्थायी और सुरक्षित आवास आज भी होता। स्मारक और समाधियां इतनी हैं दिल्ली के कि कई लोग दिल्ली को मुर्दों का शहर कहते हैं मजाक में, लेकिन जिस तरह सरकारी जमीन का फिजूल इस्तेमाल हो रहा है देश की राजधानी में, वह मजाक नहीं, गंभीर मसला है। मंत्रियों और सांसदों को हमने बताया है ऐसी कोठियों में, जिनकी कीमत बाजार में कम से कम पांच सौ करोड़ रुपए है। ऊपर से यह भी ध्यान में रखिए कि राष्ट्रपति भवन के

बाग-बगीचे 300 एकड़ जमीन पर हैं। क्या राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए 300 एकड़ जरूरी है?

सवाल और भी निकल रहे हैं उस पिटारे से। मंत्रियों को अगर इस देश की गरीब जनता के पैसें से बसाना ठीक समझती है भारत सरकार, तो क्यों नहीं इनको राष्ट्रपति भवन की 300 एकड़ जमीन पर कोठियां बनाकर बसाया जाए? रही बात सांसदों की, तो उनके लिए कई सरकारी होटल हैं



संसद के आसपास, जिनमें इतने कम ग्राहक आते हैं कि आधे खाली रहते हैं साल भर। इनमें सांसदों के लिए जगह बन सकती है उन महीनों के लिए जब संसद का सत्र चल रहा होता है। उनको क्यों बड़ी-बड़ी कोठियों की जरूरत है? अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री आवास स्थायी और सुरक्षित होना चाहिए। न कि ऐसा घर, जिसको जब किसी के मन में आए स्मारक बना दिया जाए। विनम्रता से प्रधानमंत्री को सुझाव देना चाहती हूं कि जब तक उनकी नई कोठी तैयार

नहीं होती है इंडिया गेट के पास, वे क्यों नहीं तीनमूर्ति भवन में रहना शुरू करें, नेहरू स्मारक को कहीं और बनवाकर। तीनमूर्ति भवन शानदार भी है और सुरक्षित भी।

युद्ध के इस दौर में जब प्रधानमंत्री ने गरीबों को खर्चा कम करने के लिए कहा है, तो क्यों नहीं अपनी सरकार को ऐसा करने का आदेश देते हैं? जितनी फिजूलखर्ची हम करते हैं मंत्रियों के काफिलों और कोठियों पर, इसको बंद करना क्या ‘देशभक्ति’ नहीं होगी मुसीबत के इस दौर में? लुटियंस दिल्ली की जमीन भारत में सबसे महंगी मानी जाती है, तो क्यों नहीं इसका व्यावसायिक इस्तेमाल हो? इस तरह की शुरुआत अगर दिल्ली में होगी, तो राज्यों में भी होने लगेगी और खूब पैसा बचेगा देश का।

फिलहाल प्रधानमंत्री के कहने पर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं उनके मुख्यमंत्री और मंत्री। कभी किसी मुख्यमंत्री की पत्नी साइकिल पर सवार होकर निकलती है टीवी पत्रकारों के सामने, तो कभी कोई मुख्यमंत्री स्कूटर पर सवार होकर निकलते हैं पत्रकारों को दिखाने के लिए। जब आर्थिक संकट पूरे देश में आया है, तो इस तरह के तमाशे बंद होने चाहिए और सरकारी अफसरों और राजनेताओं को दिल लगाकर देश का पैसा बचाने की कोशिश करनी चाहिए। यही होगी असली देशभक्ति। कहा था न मैंने कि जिमखाना क्लब बंद होने से खुल गया है सवालों का बहुत बड़ा पिटारा। ( यह लेखक के अपने विचार हैं )

## दिल्ली अग्निकांड से लें सबक, होटल में रुकने से पहले जान लें ये सुरक्षा नियम

**(अभिनय आकारा )**

जांचकर्ता यह पता लगा रहे हैं कि क्या प्रतिष्ठान ने सुरक्षानियमों का उल्लंघन किया और क्या उसके संचालन से परिसर में आग लगने का खतरा बढ़ गया था। जिस आराम और मानसिक शांति की तलाश में हम अपने घरों से दूर घूमने निकलते हैं, वह सफर हमारे लिए इस कदर खतरनाक साबित हो सकता है। यह दिल्ली की घटना ने साफ कर दिया है। बुकिंग करते समय



रेंटिंग और कमरों की सजावट देखने के साथ-साथ होटल के सेफ्टी मेजर्स ( फायर एग्जिट, स्मोक अलार्म ) की भी उतनी ही पड़ताल होनी चाहिए।

दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत हो गई। इस घटना की जांच में अवैध रेस्तरां, तहखाने में बंद ग्रिल, छोटी खिड़कियां और पर्याप्त निकासी मार्गों का अभाव प्रमुख चिंता के विषय बनकर उभरे हैं। होज रानी के घनी आबादी वाले इलाके में स्थित बहुमंजिला इमारत फ्लोरिश स्टे भी एंड बी में आग लगने के कुछ घंटों बाद ही जांचकर्ताओं ने कई संदिग्ध खामियों की पहचान की, जिनमें होटल का निर्धारित क्षमता से अधिक संचालन, तहखाने में आने-जाने की अपर्याप्त व्यवस्था, निकासी में बाधा डालने वाली छोटी छतरे की खिड़कियां और कथित तौर पर आवश्यक अनुमतियों के बिना संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं।

अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या इमारत की तंग जगह और आसपास बिछी बिजली की तारों ने अग्निशमन और बचाव कार्यों में बाधा डाली। इमारत के भूतल पर चल रहे रेस्तरां के पास आवश्यक लाइसेंस नहीं था और आरोप है कि वह अवैध रूप से संचालित हो रहा था। अग्निशमन

बुकिंग करते समय रेंटिंग और कमरों की सजावट देखने के साथ-साथ होटल के सेफ्टी मेजर्स ( फायर एग्जिट, स्मोक अलार्म ) की भी उतनी ही पड़ताल होनी चाहिए।

**होटल रूप में एंट्री करते ही करें ये काम** – जब भी हम किसी होटल में चेक- इन करते हैं, तो अक्सर हमारा ध्यान रूम के व्यू, बेड या एमिनटीज पर होता है। लेकिन अगली बार जब आप किसी होटल के कमरे में कदम रखें, तो अपना सामान रखने के बाद सिर्फ 2 मिनट अपनी सुरक्षा के लिए जरूर निकालें। यह छोटी सी आदत किसी भी आपातकाल में आपकी जान बचा सकती है।

**इवेक्युएशन मैप को समझें** – हर सिर्फ 2 मिनट अपनी सुरक्षा के लिए जरूर निकालें। यह छोटी सी आदत किसी भी आपातकाल में आपकी जान बचा सकती है। **इवेक्युएशन मैप को समझें** – हर इमरजेंसी इवेक्युएशन मैप ( निकासी का नक्शा ) लगा होता है. इसे ध्यान से देखें और समझें कि आपके रूम से सबसे नजदीकी बाहरी एग्जिट ( आपातकालीन निकासी ) किस दिशा में है। सुरक्षा उपकरणों की जांच-कमरे की छत पर लगे स्मोक डिटेक्टर और वॉटर स्प्रेक्लर पर एक नजर जरूर डालें कि वे ठीक स्थिति में हैं या नहीं।

**रास्ते की बाधाओं पर नजर** – अगर आपको दिखे कि इमरजेंसी सीढ़ियों या एग्जिट गेट के रास्ते में होटल स्टाफ ने गद्दे, कुर्सियां या कोई पुराना कबाड़ रख रखा है, तो तुरंत रिसेशन या मैनेजर से शिकायत कर उसे साफ करवाएं।







### संक्षिप्त समाचार

### अमेरिकी सीनेट में बड़ा फैसला: इमिग्रेशन फंडिंग बिल पर आगे बढ़ी बहस

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी सीनेट में इमिग्रेशन प्रवर्तन एजेंसियों को मजबूत करने के लिए



लगभग 70 अरब डॉलर के एक बड़े फंडिंग बिल पर बहस शुरू हो गई है। इस बिल को आगे बढ़ाने से पहले ट्रंप प्रशासन से जुड़े विवादित सेटलमेंट फंड और व्हाइट हाउस सुरक्षा प्रस्ताव को हटा दिया गया है। सीनेट ने बुधवार को 53-46 के वोट से इस विधेयक पर औपचारिक बहस शुरू करने की मंजूरी दी। यह फंडिंग मुख्य रूप से इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट और बॉर्डर पैट्रोल के लिए प्रस्तावित है। राजनीतिक खंडितान के बीच आगे बढ़ा बिल रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व में यह बिल कई हफ्तों तक अटका रहा, क्योंकि व्हाइट हाउस और कुछ विवादित प्रस्तावों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी। अब इन प्रावधानों को हटाकर इसे इसके मूल स्वरूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। सीनेट मेजॉरिटी लीडर जॉन थ्यून ने कहा कि प्राथमिक लक्ष्य अब इस बिल को जल्द से जल्द पास कराना है। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि आगे संशोधन प्रस्तावों की लंबी श्रृंखला मतदान प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बना सकती है। डेमोक्रेटिक पार्टी इस बिल पर कई संशोधन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। खासतौर पर ट्रंप के उस 1.776 अरब डॉलर के सेटलमेंट फंड को स्थायी रूप से रोकने की मांग की जा रही है, जिसे प्रशासन ने हाल ही में वापस ले लिया था। सीनेट अल्पसंख्यक नेता चक शूमर ने कहा कि उन्हें आश्चंका है कि यह फंड भविष्य में फिर से सामने आ सकता है, इसलिए इसे कानून में स्पष्ट रूप से रोकना जरूरी है। हालांकि कई रिपब्लिकन सांसदों ने इस फंड को लेकर संतोष जताया है, लेकिन कुछ अभी भी चिंतित हैं। सांसद थॉम टिलिस ने कहा कि वह ऐसा संशोधन पेश करेंगे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य में यह सेटलमेंट फंड दोबारा लागू न किया जा सके। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर पर्याप्त समर्थन है, लेकिन अंतिम वोट से पहले सहमति जरूरी होगी।

### ट्रंप बैठक में सो रहे थे?: अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति की सेहत पर विवाद

वाशिंगटन डीसी, एजेंसी। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेहत और कार्यक्षमता को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। बुधवार को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) की विदेश मामलों की समिति की सुनवाई के दौरान विदेश मंत्री मार्को रूबियो और डेमोक्रेट सांसद टेड लियो के बीच तीखी बहस देखने को मिली। सुनवाई के दौरान टेड लियो ने कई वीडियो विलप दिखाते हुए दावा किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आधिकारिक बैठकों के दौरान सोते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने एक कैबिनेट बैठक का वीडियो दिखाया, जिसमें ट्रंप की आंखें बंद और सिर झुका हुआ नजर आ रहा था, जबकि उनके बगल में बैठे मार्को रूबियो बोल रहे थे। रूबियो ने आरोपों पर क्या जवाब दिया? लियो ने रूबियो से पूछा कि क्या उन्होंने कभी ट्रंप को सरकारी बैठकों के दौरान सोते हुए देखा है। इस पर रूबियो ने आरोपों को सिर से खारिज करते हुए कहा कि वह पूरी तरह गलत है। मैंने उन्हें कभी सोते हुए नहीं देखा। सच तो यह है कि वह बहुत कम सोते हैं। वह मुझे रात 2 बजे और सुबह 5 बजे भी फोन कर लेते हैं। इसके बाद लियो ने एक और वीडियो दिखाया और दावा किया कि ट्रंप कैबिनेट बैठक के दौरान झपकी लेते नजर आए। उन्होंने कहा कि जब युद्ध और शांति जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, तब राष्ट्रपति सो रहे थे। हालांकि रूबियो लगातार इन दावों को नकारते रहे। उन्होंने कहा कि ट्रंप कभी किसी ब्रीफिंग में नहीं सोए और यह आरोप बेतुका और हास्यास्पद है। रूबियो ने राष्ट्रपति को सजाव करते हुए कहा कि ट्रंप दिन-रात लंबे समय तक काम करते हैं और कई विदेशी दौरों पर उठते-उठे पूरी उड़ान के दौरान जागते हुए देखा है। इस पर टेड लियो ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झूठ बोलते रहिए, बस झूठ बोलते रहिए।

### ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पूरा हुआ: मार्को रूबियो का दावा- खत्म हुआ ईरान युद्ध, अमेरिका ने हासिल किए अपने लक्ष्य

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बुधवार को दावा किया कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त हो चुका है, जबकि क्षेत्र में अब भी घातक हमले जारी हैं। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के समक्ष रूबियो ने कहा कि हम अब ईरान के भीतर उसकी सैन्य क्षमता को सफाजोर करने के लिए लगातार हमले नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ खत्म हो चुका है। अमेरिका और इस्राइल के इस युद्ध को वॉशिंगटन ने ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ नाम दिया था। 128 फरवरी को ईरान पर पहले हमले के बाद से यह संघर्ष पूरे पश्चिम एशिया में फैल गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाया और खाड़ी के तेल और गैस परिवहन के प्रमुख मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य को प्रभावी रूप से बंद कर दिया। रूबियो ने कहा कि अमेरिका ने अपने सभी सैन्य लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। उनके अनुसार, ईरान के रक्षा औद्योगिक ढांचे को नष्ट किया गया, उसके मिसाइल लॉन्चरों और ड्रोन भंडार को भारी नुकसान पहुंचाया गया, जबकि उसकी बची हुई वायुसेना और पारंपरिक नौसेना को भी खत्म कर दिया गया। हालांकि, डेमोक्रेट सांसदों ने रूबियो के इस दावे का विरोध किया और कहा कि संघर्ष अभी भी जारी है। बुधवार को ईरान ने कुवैत के हवाई अड्डे पर हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 63 लोग घायल हो गए। इसे संघर्ष में बड़ा उछाल माना जा रहा है। वहीं, बहरैन में भी रातभर ईरानी ड्रोन हमले हुए। बहरैन और कुवैत दोनों देशों में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी है। कैलिफोर्निया से डेमोक्रेट सांसद सारा जैकब्स ने रूबियो से कहा कि आप ऑपरेशन का नाम बदल सकते हैं, लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि होर्मुज जलडमरूमध्य अब भी बंद है।

# पाकिस्तान के भाईजान को भारत ने नहीं दिया भाव, अब संबंध सुधारने की कोशिशें कर रहा तुर्किये

**सिंगापुर, एजेंसी।** कश्मीर से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के मामले तक तुर्किये हर मौके पर पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया है। इसके चलते भारत के साथ तुर्किये के संबंध बिगड़े हैं। हालांकि, तुर्किये के रुख में कोई खास बदलाव नजर नहीं आया है, लेकिन अब वह भारत से संबंधों को सुधारने की कोशिश में जुटा है। तुर्किये ने कहा कि हम इकलौते देश नहीं हैं, जिसके पाकिस्तान के साथ अच्छे और भाईचारे के संबंध हैं, दुनिया में ऐसे संबंधों वाले अन्य देश भी हैं।

सिंगापुर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटैजिक स्टडीज (आईआईएसएस) के कार्यक्रम में बुधवार (तीन जून) को तुर्किये के विदेश मंत्री हकान फिदान ने भारत आग्रह किया कि वे अंकारा और नई दिल्ली के संबंधों को पाकिस्तान को सामने रखते हुए न देखे। वहीं, उन्होंने



### भारत के संबंधों को सुधारने की दिशा में कदम

हकान फिदान ने इस बात पर जोर दिया कि तुर्किये के पास भारत के साथ अच्छे संबंध रखने की पर्याप्त वजह हैं।

# भारतीय शख्स पर गर्भवती किशोरी और अजन्मे बच्चे की हत्या का आरोप

### पीड़ित परिवार ने की निर्वासन की मांग

**ओहियो, एजेंसी।** अमेरिका के ओहियो में एक दर्दनाक कार दुर्घटना में अपने अजन्मे बच्चे के साथ मारी गई एक गर्भवती किशोरी की हत्या का आरोप एक भारतीय शख्स पर लगा है। किशोरी की मां एनेट होम्स ने भारतीय व्यक्ति को देश से निर्वासित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वह 33 वर्षीय तरसेम सिंह को देश में नहीं रहने देना चाहती। पीड़िता के परिवार के अनुसार, अमेरिका में अवैध रूप से रह रहा भारतीय नागरिक तरसेम सिंह 17 वर्षीय ऐश्ली होम्स के अजन्मे बच्चे का पिता था। रिश्तेदारों ने बताया कि ऐश्ली ने कई बार इस रिश्ते से अलग होने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। एनेट होम्स ने कहा, ‘किस्ती को भी अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती होने के दौरान नहीं मरना चाहिए।’ उन्होंने आगे कहा, ‘मुझे अच्छा लगेगा, अगर उसे स्थायी रूप से देश से निकाल दिया जाए। हमें पता चला कि वह पहले अवैध रूप से यहां आया था। वे उसे कहीं भी भेज सकते हैं जहां वह सबसे अच्छा हो क्योंकि मैं उसे अब अमेरिका में नहीं चाहती।’ पुलिस के अनुसार, 16 फरवरी को हुई दुर्घटना के समय ऐश्ली रेंज



रोवर में एक यात्री के रूप में सवार थी। अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना तब हुई, जब आरोपी तरसेम सिंह कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा रोके जाने पर नहीं रुके। इसके बाद करीब 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी भगाने के दौरान एक भीषण टक्कर के चलते उनका पीछा करना खत्म हुआ। ओहियो स्टेट हाईवे पेट्रोल की दुर्घटना रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया है कि रेंज रोवर को शुरू में 55 मील प्रति घंटे के क्षेत्र में 79 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भागा गया था। वहीं, पीछा करने के दौरान यह गति 120 मील प्रति घंटे से अधिक हो गई। पलटने से पहले एक जीप से टकरा गई। दुर्घटना के बाद ऐश्ली कार से बाहर गिर गई। ओहियो स्टेट हाईवे पेट्रोल की दुर्घटना रिपोर्ट के अनुसार, उसे घातक चोटें आई थी। इसके चलते ऐश्ली और उसके अजन्मे बच्चे की भी मौत हो गई। इस बीच आईसीई ने 33 वर्षीय सिंह को नजरबंदी में रखा है। उस पर गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से हत्या और गंभीर वाहन दुर्घटना में हत्या सहित कई अपराधिक मामलों में गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

### सैमसंग ने एआई पावर वाले रोज़ाना के हेल्थ कंपैनियन के लिए नए गैलेक्सी वॉच फीचर्स लॉन्च किए

**सेओल, कोरिया।** सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड ने आज सैमसंग हेल्थ ऐप के लिए एक बड़े अपडेट की घोषणा की है, जो आने वाली गैलेक्सी वॉच को एक सक्रिय और समझदार हेल्थ पार्टनर में बदल देगा। 8 जून से सैमसंग इस ऐप अपडेट को रोल आउट करना शुरू कर देगा ताकि आगामी गैलेक्सी वॉच में मिलने वाले मुख्य हेल्थ फीचर्स की झलक दिखाई जा सके। यह अपडेट रात की नींद से लेकर दिनभर की गतिविधियों तक के जटिल बायोमेट्रिक डेटा को सरल और काम आने वाले सुझावों में बदलकर रोज़ाना के स्वास्थ्य प्रबंधन को बहुत आसान बना देता है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के मोबाइल एक्सपीरियंस (MX) बिजनेस में डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र के सीनियर वाइस प्रेजिडेंट और हेड, होन पाक ने कहा, ‘सैमसंग हेल्थ ऐप अब गैलेक्सी वॉच द्वारा मापे गए हेल्थ डेटा को एआई आधारित जानकारीयों से जोड़ने के लिए विकसित हो रहा है। इससे यूजर्स अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को अधिक आसानी से और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्टेड गैलेक्सी इकोसिस्टम और डिजिटल हेल्थ इन्ोवेशन्स के आधार पर सक्रिय और व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रबंधन के अनुभवों का विस्तार करना जारी रखेगा। यह प्रगति वास्तव में एआई-संचालित हेल्थ प्लेटफ़ॉर्म के लिए सैमसंग के व्यापक दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसे यूजर्स को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और आगे रहने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नए घोषित हेल्थ फीचर्स सबसे पहले आने वाली गैलेक्सी वॉच पर उपलब्ध होंगे।

गैलेक्सी वॉच को इंटेलीजेंट हेल्थ पार्टनर में बदलने वाले फीचर्स **सैमसंग हेल्थ अपडेट इन फीचर्स के साथ आया है:** वाइटल्स: शरीर के संकेतों को बेहतर समझ – पहले, सैमसंग हेल्थ यूजर्स के दैनिक एनर्जी स्कोर को मापने में मदद करने के लिए कुछ खास हेल्थ मेट्रिक्स की निगरानी करता था। अब सैमसंग हेल्थ इसमें एक कदम आगे बढ़ रहा है। जब यूजर्स सुबह जागते हैं, तो नया ‘वाइटल्स’ फीचर रात के समय के पांच प्रमुख बायो-मेट्रिक्स ड्रू हार्ट रेट, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, रैस्पिरैटरी रेट, स्किन टेम्परेचर और ब्लड ऑक्सीजन ड्रू का उनके वास्तविक रैरिटिंग बेसलाइन के साथ विश्लेषण करता है। यह केवल तभी नोटिफ़िकेशन भेजता है जब इसे कोई महत्वपूर्ण बदलाव मिलता है। इससे यूजर्स को यह तय करने में मदद मिलती है कि उन्हें अधिक आराम की आवश्यकता है या वे किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, और वे बार-बार आने वाले फलतू अलर्ट्स से परेशान नहीं होते।

# ईरानी हमलों में अमेरिकी सैनिकों की हुई मौत तो खत्म हो जाएगा युद्धविराम

**तेहरान, एजेंसी।** कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल हुए भारतीयों से मिलने के लिए भारतीय राजदूत परमिता त्रिपाठी बुधवार को अस्पताल पहुंचीं। उन्होंने घायलों को दूतावास की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। कुवैत के हवाई अड्डे पर हुए हमलों में एक भारतीय शख्स ने भी जान गंवाई थी। भारतीय दूतावास ने कहा कि वह मृतक भारतीय नागरिक के परिवार के संपर्क में है और पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द वापस भेजने के लिए कुवैती अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। भारत ने बुधवार को कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए ड्रोन हमले की कड़ी निंदा की। इन हमलों में एक भारतीय नागरिक की जान चली गई और कई अन्य भारतीय घायल हो गए। भारत ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए अपनी आवाज उठाई।

वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निजी तौर पर अपने सहयोगियों से कहा है कि अगर तेहरान अमेरिकी सैनिकों की मौत के लिए जिम्मेदार होता है तो वह ईरान के साथ युद्धविराम समाप्त करने के बारे में सोचेंगे। अधिकारियों ने कहा कि ट्रंप ने यह स्पष्ट कर दिया है कि क्षेत्र में जारी हिंसक झड़पों और तनाव के बावजूद हवाई हमलों में कई हफ्तों का विराम प्रभावी बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार,



झड़पें जारी हों। अधिकारियों ने सुझाव दिया कि ट्रंप पश्चिम एशिया में व्यापक युद्ध का जोखिम उठाने के बजाय कुछ हफ्तों या महीनों तक छोटी-मोटी झड़पों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो सकते हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने दावा किया है कि उसकी नौसेना ने ओमान सागर में एक अमेरिकी सैन्य पोत को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह कार्रवाई अमेरिकी गतिविधियों और समुद्री नियमों के कथित उल्लंघन के जवाब में की गई। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस दावे को भी तुरंत खारिज कर दिया। अमेरिका का कहना है कि ईरान द्वारा लगाए गए आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं और अमेरिकी नौसेना के किसी पोत को नुकसान नहीं पहुंचा है। कुवैत

अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि एयरपोर्ट को नुकसान अमेरिकी मिसाइल इंटरसेप्टर के कारण हुआ। अमेरिकी सेना का कहना है कि यह दावा पूरी तरह गलत है। उनके अनुसार, नागरिक हवाई अड्डे को निशाना बनाकर ड्रोन हमला किया गया था और यह सुनिश्चित कार्रवाई थी। इस घटना में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई, जबकि कई अन्य लोग घायल बताए गए हैं। लेबनान सीमा पर जारी तनाव के बीच इस्राइल के सेना प्रमुख ने स्पष्ट संकेत दिया है कि मौजूदा हालात को वास्तविक युद्धविराम नहीं माना जा सकता। उनका कहना है कि सीमा क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं और सैन्य सतर्कता पहले की तरह जारी है। इस्राइली सेना प्रमुख इयाल जामीर ने हाइफा स्थित नौसैनिक अड्डे के दौरे के दौरान यह टिप्पणी की। उनका बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका की मध्यस्थता में इस्राइल और लेबनान के बीच वार्ता का नया दौर चल रहा है। हालांकि इन प्रयासों को लेबनान के शक्तिशाली संगठन हिजबुल्लाह का विरोध झेलना पड़ रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य ईरान के साथ किसी भी संभावित युद्ध को रोकना और राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करना है।

### भारत बोला- सहयोगको प्रतिबद्ध, इस साल के अंत में पांच सदस्यों की विदाई

संयुक्त राष्ट्र, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, जिनिदाद और टोबैगो, तथा जिम्बाब्वे को 2027-28 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूपएएससी) के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में चुना है। भारत ने इन देशों को बहाई देते हुए उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में इनके साथ करीबी सहयोग होगा। बुधवार देर रात हुए इस चुनाव में 193 सदस्यीय महासभा ने पांच नए गैर-स्थायी सदस्यों का चुनाव किया गया। गौरतलब है कि 2026 के अंत में डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया की जगह लेंगे। भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने एक्स ट्विटर पर लिखे आधिकारिक संदेश में नए सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि भारत इन देशों के साथ काम करने की इच्छा रखने के अलावा उत्सुक भी है। बता दें कि गोपनीय मतदान के माध्यम से चुने गए इन सदस्य देशों का कार्यकाल 1 जनवरी 2027 से 31 दिसंबर 2028 तक रहेगा। पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों के समूह में जर्मनी को बड़ा झटका लगा, जहां उसने 104 वोट प्राप्त किए, जबकि पुर्तगाल को 134 और ऑस्ट्रिया को 131 वोट मिले। परिणामों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूपएजीए) की अध्यक्ष और पूर्व जर्मन विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक ने की। जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वेडेकुल ने इस परिणाम को ‘वास्तविक निराशा’ बताया। उन्होंने कहा कि जर्मनी ने देर से चुनाव में भाग लिया, जिससे उसे नुकसान हुआ। उन्होंने यूक्रेन के प्रति समर्थन और इस्राइल के संबंध में जर्मनी की स्पष्ट स्थिति को भी चुनावी हार का कारण बताया। अफ्रीका और एशिया-प्रशांत राज्यों के दो पदों के लिए दक्षिण पूर्व अफ्रीका में बसे देश जिम्बाब्वे को 182 और किर्गिस्तान को 142 वोट मिले। किर्गिस्तान पहली बार सुरक्षा परिषद में शामिल होगा। उसने फिलीपींस को 142-49 के अंतर से हराया। लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई राज्यों के समूह में त्रिनिदाद और टोबैगो को 181 वोट मिले।

### इमरान खान की रिहाई को लेकर उनकी ही पार्टी में बगावत, कई विधायक बोले- बयानबाजी से नहीं आएंगे जेल से बाहर

पेशावर (पाकिस्तान), एजेंसी। पाकिस्तान की सतारूढ़ पार्टी पाकिस्तान तारीक-ए-इंसाफ में आंतरिक कलह खुलकर सामने आ गई है। खैबर पख्तूनख्वा के कई नाराज विधायकों ने पार्टी नेतृत्व पर तीखा हमला बोलते हुए जेल में बंद संस्थापक इमरान खान की रिहाई के लिए प्रभावी प्रयास नहीं करने का आरोप लगाया है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, हालिया कैबिनेट विस्तार में पद नहीं मिलने से नाराज विधायकों ने पेशावर में एक आपात बैठक की और पार्टी अध्यक्ष बैरिस्टर गोहर अली को एक पत्र भेजा। पत्र में कहा गया कि इमरान खान की रिहाई और उनके स्वास्थ्य को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में गहरी चिंता है। विधायकों ने आरोप लगाया कि इमरान खान की रिहाई के लिए चलाया जा रहा आंदोलन केवल बयानबाजी, सीमित विशेष प्रदर्शनों और प्रतीकात्मक गतिविधियों तक सिमटकर रह गया है। उन्होंने नेतृत्व से अधिक प्रभावी, संगठित और परिणाम देने वाली नई रणनीति बनाने की मांग की। पत्र में खैबर पख्तूनख्वा सरकार के कामकाज पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। विधायकों ने भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, संसाधनों के कथित अनुचित वितरण और निर्वाचित प्रतिनिधियों से बिना सलाह लिए फैसले करने के आरोप लगाए। उन्होंने प्रशासन में पारदर्शिता, योग्यता आधारित व्यवस्था और संस्थागत अनुशासन लागू करने की मांग की। नाराज नेताओं ने स्पष्ट किया कि वे इमरान खान की विचारधारा और पार्टी के विजन के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं व किसी गुट या व्यक्ति विशेष के एजेंडे का हिस्सा नहीं हैं। साथ ही उन्होंने इमरान खान समेत जेल में बंद पार्टी नेताओं और कासकतों के लिए प्रभावी कानूनी सहायता तथा उनके परिवारों के समर्थन की व्यवस्था करने की भी मांग की।



# स्थानीय चुनाव में 12 प्रांत जीते, फिर भी अधूरी रही खुशी

**सियोल, एजेंसी।** दक्षिण कोरिया में बुधवार को हुए स्थानीय चुनावों में राष्ट्रपति ली जे म्युंग की सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी ने अधिकांश सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन राजधानी सियोल के मेयर पद की सबसे अहम लड़ाई हार गई। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह परिणाम राष्ट्रपति ली के लिए मिला-जुला संदेश है, क्योंकि उनकी पार्टी ने बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन सबसे प्रतिष्ठित चुनावी मुकामला गंवा दिया।

करीब सभी मतों की गिनती पूरी होने तक डेमोक्रेटिक पार्टी ने 16 में से 12 मेयर और प्रांतीय गवर्नर पदों पर जीत दर्ज की। वहीं मुख्य विपक्षी पीपुल पावर पार्टी ने चार सीटें जीतीं, जिन्में सियोल मेयर का पद भी शामिल है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जॉंग चुंग-रान ने सियोल में हार को दर्दनाक बताया, हालांकि अन्य क्षेत्रों में मिली जीत के लिए मतदाताओं का आभार जताया।

राष्ट्रपति ली के एक वर्ष पूरे होने के दिन हुआ चुनाव यह चुनाव राष्ट्रपति ली के कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने के दिन हुआ। ली को अभी भी 60 प्रतिशत से अधिक जनसमर्थन प्राप्त है। उनकी सरकार को अमेरिका और जापान के साथ संबंधों को संतुलित रखने वाली व्यावहारिक



सियोल मेयर पद पर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार चोंग वोन-ओ शुरुआती रङ्गानों में आगे थे, लेकिन मतगणना आगे बढ़ने के साथ मौजूदा मेयर ओह से-हून ने बढ़त बना ली और अंततः जीत दर्ज की। जीत के बाद ओह से-हून ने कहा कि सियोल के नागरिकों ने यह सुनिश्चित किया है कि देश किसी एक दिशा में अत्यधिक न झुके और लोकतंत्र का संतुलन बना रहे। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार चोंग वोन-ओ ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि वे जनता के

फैसले को विनम्रता से स्वीकार करते हैं। चुनाव के दौरान सियोल के कुछ मतदान केंद्रों पर मतपत्रों की कमी के कारण मतदान अस्थायी रूप से रोकना पड़ा, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। पीपीपी ने इस घटना को मतदाताओं के अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए जांच के आधार पर दोबारा चुनाव कराने की मांग की, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसे खारिज कर दिया। इस बीच, संसद के उपचुनावों में भी डेमोक्रेटिक पार्टी ने 14 में से नौ सीटें जीतकर अपनी संसदीय बढ़त और मजबूत कर ली। हालांकि सबसे चर्चित जीत पूर्व पीपीपी नेता हान डोंग-हून की रही, जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बुसान से जीत दर्ज की। हान डोंग-हून ने जीत के बाद कहा कि वे दक्षिण कोरिया के रूढ़िवादी खेमे का पुनर्निर्माण करेंगे और सरकार पर लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखने का दबाव बनाए रखेंगे। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि स्थानीय स्तर पर डेमोक्रेटिक पार्टी की बढ़ती पकड़ राष्ट्रपति ली को क्षेत्रीय नीतियों को लागू करने में मदद करेगी, लेकिन सियोल की हार यह संकेत देती है कि विपक्ष अभी भी देश की राजनीति में महत्वपूर्ण ताकत बना हुआ है।







स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आशिष कुमार कंठले द्वारा कलियुग का भारत द्वारा अग्रदूत कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, भाजपा कार्यालय के पास, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित एवं वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा पोस्ट व जिला बेमेतरा छ.ग. पिन कोड 491335 से प्रकाशित। संपादक आशिष कुमार कंठले समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार मो. नं. 7999238079, 7828658259, समस्त विवादों का निपटारा बेमेतरा न्यायालय होगा।